शिक्षा एवं बहुसंस्कृतिवाद-I

क्रिस्टोफर विंच और जॉन गिंगेल
अनुवाद : रमणीक मोहन

इस अध्याय में हम इस मुद्दे से संबोधित होंगे कि एक उदारवादी लोकतांत्रिक समाज के भीतर रहते हुए एक शिक्षा-व्यवस्था भिन्न-भिन्न प्रकार के मूल्यों और जीने के तरीकों के लिए किस तरह गुंजाइश और स्थान बना सकती है। इस मुद्दे को ले कर विभिन्न व्यापक दृष्टिकोणों का जायजा लेने के बाद हम अपनी चर्चा को मूल्य-विविधता, नागरिकता और स्वायत्तता से संबंधित दृष्टिकोणों के साथ संबद्ध करेंगे। इसके बाद हम इस मुद्दे पर कुछ समकालीन उदारवादी प्रतिक्रियाओं पर नजर डालते हैं और सामुदायिकता वाद या समुदाय-विशेष के मूल्यों को सार्वजनिक मूल्यों पर प्राथमिकता दिए जाने के मुद्दे पर चर्चा करेंगे। अन्त में एक केस स्टडी के तौर पर हम युनाइटिड किंगडम में धार्मिक स्कूलों से संबद्ध बहस पर एक विस्तृत नजर डालते हुए दर्शाएंगे कि यह कितना जटिल मुद्दा है। उसके बाद इसके समाधान के लिए अपने सुझाव देते हैं। हमने धार्मिक स्कूलों की शिक्षा को इसलिए चुना है क्योंकि यह संबद्ध मुश्किल मुद्दों को उदाहरण के तौर पर दर्शाती प्रतीत होती है और इसलिए भी कि इस सवाल की समकालीन प्रासंगिकता एक से अधिक देशों में है।

राजनैतिक एवं शैक्षिक उदारवाद

ऐसा सोचा जा सकता है कि शिक्षा के भीतर बहुसंस्कृतिवाद से संबद्ध किसी अध्याय में मानव प्रजातीय (Ethnic) विविधता और शिक्षा में उसके प्रभाव को केन्द्र में होना चाहिए। लेकिन एक पल का सोच-विचार ही यह स्पष्ट करने के लिए काफी है कि किसी व्यक्ति या समूह की प्रजातीय पहचान का शिक्षा और शिक्षा नीति के सवालों से कुछ विशेष लेना-देना नहीं है। मुद्दा स्वयं में उनकी मानव प्रजाति का नहीं है बल्कि समाज तथा उस राज्य के साथ एक व्यक्ति या समूह की संस्कृति और मूल्यों के रिश्ते का है, जिसके लिए वे प्रतिबद्ध हैं। इस सवाल को लेकर आधुनिक शिक्षा-व्यवस्था में मोटे तौर पर तीन तरह के दृष्टिकोण अपनाए गए हैं। पहला दृष्टिकोण तो 'प्रजातीय-अलगाव समाप्ति' का, सम्मिलित हो जाने, रच-बस जाने का है। इसका अर्थ है कि अल्पसंख्यक समूहों को मेजबान समुदाय की जीवन-शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, यहां तक कि इसके लिए दबाव में भी बनाया जाए।

दूसरा दृष्टिकोण 'एकीकरण' का, जुड़ाव-मिलान का है। यहां वकालत की जाती है कि अल्पसंख्यक समूह नागरिक-मानकों एवं आचार-व्यवहार का पालन करें- जैसे कि कानून, राजनैतिक व्यवस्था और आर्थिक संबंधों का सम्मान- साथ ही मेजबान समुदाय की भाषा को भी अपनाएं, कम से कम घरेलू परिस्थिति के बाहर तो जरूर ही। एकीकरण का हिमायती नज़रिया मानता है कि बच्चे चाहें तो परिपक्व होने पर अपने समूह में स्थापित जीवन-शैली से बाहर निकलने का अर्थपूर्ण विकल्प उनके पास मौजूद रहे। इसका अर्थ है कि वे स्वायत्त हैं और उनकी शिक्षा को उन्हें स्वायत्त होने के लिए तैयार करना चाहिए (बर्टन्वुड, 2002)।

तीसरे नजरिए को कभी-कभी 'बहुसांस्कृतिक' कहा जाता है। बहुसंस्कृतिवाद के समर्थक इस सवाल को लेकर दुविधा में रहते हैं कि अल्पसंख्यकों को मेजबान समाज की प्रथाओं और मूल्यों को अपनाना चाहिए कि नहीं। वे इस दृष्टिकोण की ओर प्रवृत्त रहते हैं कि समुदायों को अपनी जीवन-शैली, जितना वे चाहें, बचा कर रखने का अधिकार है।

हमारा तर्क रहेगा कि एकीकरण का कोई रूप या संस्करण उदारवादी लोकतन्त्रों के लिए सबसे अधिक वांछित नजरिया है। प्रजातीय समुदायों को अपनी जीवन-शैली त्यागने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए लेकिन मेजबान समाज के साथ वे इस तरह की गुंजाइश निकालें कि सभी नागरिकों के बीच शांति, और इससे भी बेहतर, समानता और परस्पर आदर पर आधारित सामंजस्यपूर्ण एवं उत्पादक संबंधों को बढ़ावा मिले। इस आदर्श को अभिव्यक्त करना तो आसान है मगर इसकी ओर जाने वाला रास्ता समस्याओं से भरा है। फिर भी, हमें लगता है कि यह आदर्श बढ़ावा दिए जाने लायक है। अब हम इस तक पहुंचने की कोशिश में शामिल कुछ केन्द्रीय मुद्दों की चर्चा करते हैं।

यदि संबद्ध व्यक्ति या समूह उदारवादी लोकतंत्र की बुनियाद के केन्द्रीय मूल्यों, और इसके फलस्वरूप ऐसे लोकतंत्र के भीतर शिक्षा के साथ, साझेदारी महसूस करते हैं तो उन्हें मुख्य-धारा की संस्कृति के साथ एकीकृत करने में किसी तरह की सैद्धांतिक समस्याएं नहीं आएंगी। अगर मूल्य-अन्तर या विचलन भी हो मसलन भोजन या पहनावे के तरीके को लेकर तो यह एकीकृत परिप्रेक्ष्य के अन्तर्गत सार्वजनिक नीति के लिए कोई विशेष समस्या नहीं है क्योंकि इस तरह की बातें व्यक्तिगत चुनाव का मामला हैं। समस्याएं तब ही उभर कर आती हैं जब इस तरह के मूल्य सार्वजनिक नीति के स्तर पर अन्य समूहों के मूल्यों से मेल नहीं खाते और उनके लिए चुनौती बन जाते हैं। इस तरह, इस्लाम की पृष्ठभूमि वाली लड़कियां अपने निजी जीवन में सिर ढकने का फैसला लेती हैं तो यह सार्वजनिक चिन्ता का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन, उदाहरण के लिए, अगर यह माना जाता है कि पोशाक की ऐसी शैली से स्कूलों में शिक्षा-व्यवस्था के केन्द्रीय मूल्यों को आघात पहुंचता है, क्योंकि यह व्यवस्था मूल रूप से धर्म-निरपेक्ष है, और सिर ढकने के कुछ विशेष रूपों को इस धर्म-निर्पेक्षता का उल्लंघन सोचा जाता है, तो यह सार्वजनिक बहस का और अंततः सार्वजनिक नीति का मुद्दा बन सकता है, जैसा कि फ्रांस में इस समय हो रहा है। इसी वजह से शिक्षा, उदारवादी लोकतंत्र की केन्द्रीय समस्याओं में से एक के केन्द्र में है। उदारवादी लोकतंत्र राजनैतिक आजादी और समानता के मूल्यों को स्वभावतः स्थापित करता है- बहुत हद तक वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वह विविध और कभी-कभी प्रतिद्वंद्वी हितधारक समूहों को सेवा उपलब्ध करवाने के प्रति जागरूक होता है, जो हो सकता है कि ऐसे मूल्यों का समर्थन न करते हों या न करें। ऐसे समूहों का आधार प्रजातीय हो सकता है और नहीं भी हो सकता। उदाहरण के लिए, यू.के. में धुर दक्षिणपंथी ब्रिटिश नैश्नल पार्टी के मूल्य उदारवादी लोकतंत्र के लिए उतने ही चुनौतीपूर्ण हैं जितना कि रूढ़िवादी या कट्टरपंथी इस्लाम।

इस तरह के हितधारक समूह अच्छे जीवन के आदर्शों को जन्म देते हैं, उन्हें जगह देते तथा पोषित करते हैं। ये आदर्श आत्म-निर्देशित हो सकते हैं (हम अपने लिए ऐसा ही चाहते हैं और हम इसमें किसी की ओर से कोई बाधा भी नहीं चाहते) लेकिन ये आदर्श दूसरों की ओर निर्देशित भी हो सकते हैं, बहुत बार होते भी हैं। ऐसा हम सबके लिए ही चाहते हैं और ये आदर्श हासिल करने की दौड़ में हम हर किसी को शामिल होने के लिए मनाने, फुसलाने या बाध्य करने को भी तैयार रहते हैं। इसका अर्थ है कि प्रतिस्पद्धा केवल आवश्यक पहचान और मान्यता के लिए तथा इससे हासिल होने वाले संसाधनों और प्रतिष्ठा के लिए ही नहीं होगी। यह केवल संपूर्ण लाभ में साझेदारी के लिए नहीं बल्कि प्रभाव वाले उन पदों और नियंत्रण के लिए भी होगी, जहां से लाभ के लिए तैयारी और उसके वितरण की प्रक्रियाएं भी निर्देशित होती हैं। जरूरी नहीं है कि इस तरह की महत्वाकांक्षाएं अपने स्वार्थ से ही प्रेरित होती हों। बहुत बार तो सच्चाई और परोपकारिता की भावना इस तरह के समूहों को व्यापक आमजन के जीवन को नियंत्रित करने की आकांक्षा के लिए प्ररित करती हैं। वे चाहते हैं कि हम उनके आदर्श साझा करें, इसलिए नहीं कि यह उनके लिए अच्छा है बल्कि इसलिए कि यह हमारे लिए अच्छा होगा।

उदारवादी राज्य स्वयं को इन प्रतिस्पर्द्धात्मक एवं परस्पर-विरोधी विचारधाराओं के जटिल समूह के केन्द्र में देखता है और इन विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न समूहों के बीच एक निष्पक्ष निर्णयकर्ता के रूप में काम करने की कोशिश करता है। स्वतंत्रता और समानता के लिए प्रतिबद्धता के अलावा अच्छे जीवन का उसका अपना कोई सिद्धांत नहीं है - कम से कम उसके सबसे अधिक संयमित-गम्भीर शास्त्रीय रूप में तो नहीं (जिसे हमने उसका सार्वभौम रूप कहा है)। अगर वह ऐसे किसी आदर्श का समर्थन करता है तो वह या तो अन्य विचारधाराओं के साथ प्रतिस्पद्धा में रहते हुए बस एक और विचारधारा का वाहक बन कर रह जाएगा या फिर पहले से मौजूद किसी एक विचारधारा का अनुचित तरीके से पक्ष लेगा। लेकिन इस तरह के राज्य को, उन कारणों से, जो हमने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या पर चर्चा करते हुए* बताए हैं, उसकी बुनियाद रखने वाले विभिन्न हितधारक-समूहों के बच्चों को शिक्षित करना होगा। और यही समस्या है। सर्वप्रथम तो इसलिए कि यह स्पष्ट नहीं है कि वयस्कों पर लागू होने वाले उदारवादी सिद्धांत बच्चों पर भी लागू होते हैं कि नहीं। दूसरा इसलिए कि निष्पक्षता, जिसे एक उदारवादी राज्य की विशेषता माना जाता है, शिक्षा के किसी भी पर्याप्त विचार के साथ मेल नहीं खाती मेल खाती भी है तो बहुत ही खराब तरीके से।

उदारवाद लोगों को समझदार और तर्कसंगत वयस्क मानता है। इसीलिए वह उन्हें विकल्प के चुनाव की छूट देता है और उनके द्वारा किए गए चुनाव का आदर करता है। लेकिन अगर ऐसा है तो उदारवाद के अन्तर्गत बच्चों की स्थिति समस्याग्रस्त हो जाती है। अगर ऐसे बच्चों को बस विशेष वयस्कों, जैसे कि उनके माता-पिता या किन्हीं विशेष सामाजिक समूहों, की जायदाद के तौर पर देखा जाता है, तो शायद उदारवादियों के लिए संबंध का विषय केवल इतना होगा कि ऐसी जायदाद के साथ वे वयस्क क्या करते हैं। लेकिन हमारी जानकारी में बचपन की कोई भी ऐसी पर्याप्त अवधारणा नहीं है जो बच्चों के लिए बस इतना ही सीमित रुतबा तय करती हो। आम तौर पर तो बच्चे को स्वयं में, अपने ही लिए मूल्यवान समझा जाता है और जहां भी विशेष वयस्कों को ऐसे बच्चे के लिए 'जिम्मेदार' माना जाता है, इस जिम्मेदारी को काफी हद तक संबद्ध बच्चे के स्वतंत्र हितों के संदर्भ में भुनाया जाता है। कहने का अर्थ यह कि बच्चे स्वयं चुनाव करने वाले तार्किक वयस्क बन सकते हैं और यह सुनिश्चित करना **हमारा** कर्तव्य है कि इस तरह की स्वायत्तता की ओर प्रगति बाधित न हो और **'हम'** में वे सब शामिल हैं जो शामिल हो सकते हों। इस तरह, उदाहरण के लिए, अगर इस बात पर सहमति है कि स्वायत्तता तक पहुंचने के लिए शिक्षा एक पूर्व शर्त है, तो इस शिक्षा को जबरदस्ती लागू किया जाना पड़ सकता है - बच्चे की मौजूदा इच्छा और बच्चे के लिए प्राकृतिक तौर पर जिम्मेदार लोगों की इच्छा न होने के बावजूद। सम्भवतः यह एक तरह की राजनैतिक सहमति से बनी आम राय है जिसके तहत समाज के सभी तबकों के विचारों को ध्यान में रखा गया है। और अगर यह अपने आप में शिक्षा पर लागू होता है तो शिक्षा के भागों पर भी लागू हो सकता है। मसलन, व्यापक, मेहराब-रूपी उदारवाद इस बात पर जोर दे सकता है कि जहां तक गणित और विज्ञान-शिक्षण की बात है, हम प्रतिबद्ध तौर पर अनुदारवादी हैं क्योंकि महत्वपूर्ण बात पसन्द की नहीं बल्कि ठीक समझने की है। लेकिन यह बात और अधिक विवादपूर्ण क्षेत्रों तक भी जा सकती है। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि यौन-संबंधी मुद्दों को लेकर तार्किक चुनाव कर पाने के लिए एक शर्त ऐसे विषयों में शिक्षित होना है, तो यह बच्चों को ऐसी शिक्षा देने के हक में एक बहुत प्रबल तर्क होगा। इस प्रकार, बच्चों की कोई भी उदारवादी शिक्षा उन कुछ समूहों की अभिरुचियों के विरुद्ध जा सकती है, जिन समूहों के बच्चे शिक्षित हो रहे हों।

उपरोक्त बातें बच्चों को अनगढ़, प्रशिक्षु-चुनावकर्ताओं के रूप में देखे जाने के विचार से संचालित हैं। लेकिन इन्हें स्वयं शिक्षा की प्रकृति से भी बल मिलता है। शिक्षा की सब अवधारणाएं सारतः नियामक या मानक स्थापित करने वाली होती हैं। उनमें आवश्यक तौर पर तथ्यों और मूल्यों का मिश्रण शामिल रहता है। पाठ्यचर्या-संबंधी हमारी चर्चा** में शिक्षा की विषयवस्तु की हमारी अवधारणा का वृत्तांत महत्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्यों का और समीक्षात्मक जांच-पड़ताल के मूल्य का मूर्त रूप है यानी शिक्षा की विषयवस्तु की हमारी अवधारणा इन मूल्यों का ही मूर्त रूप है, उसमें ये मूल्य ठोस रूप में हमारे सामने आते हैं,। हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हैं जिसमें बच्चों का परिचय

उस सबसे करवाया जाए जो समाज की संस्कृति में बेहतरीन है (क्योंकि उस 'बेहतरीन' का चुनाव लोकतांत्रिक आम सहमति से किया जाता है)- और उस संस्कृति पर आलोचनात्मक विचार करना भी सिखाया जाए। ये दोनों मूल्य-प्रतिबद्धताएं राज्य के अन्तर्गत कुछ घटक-समूहों को शायद रास न आएं। पहला मूल्य तो शायद इसलिए रास न आए, कि जो कुछ भी विविध रूपों में प्रस्तुत किए जाने की कोशिश होगी, वह सब संभवतः ऐसा नहीं होगा जिसे कोई घटक-समूह स्वीकारे और पसन्द करे। और दूसरा मूल्य इसलिए नहीं, कि आजकल की विशिष्ट शब्दावली में बात करें तो आलोचनात्मक चिन्तन का रुझान एक हस्तांतरित होने वाली दक्षता का है, जिसे अगर आकर्षक सांस्कृतिक रूप में परोसी जाने वाली चीजों पर लागू किया जाता है, तो उसे बच्चे के माता-पिता के समूह की संस्कृति की समझ पर भी लागू किया जा सकता है यानी उनकी यह समझ भी आलोचना के दायरे में आ सकती है।

इस तरह बच्चे की प्रकृति और शिक्षा की प्रकृति, दोनों हमें सांस्कृतिक पुनरोत्पादन मात्र से आगे तक जाने वाली शिक्षा नीतियों की ओर धकेलते हैं। सम्भव है कि ऐसी नीतियों के प्राप्तकर्ता शिक्षा के दायरे के अन्तर्गत या उनके अपने सांस्कृतिक समूहों में जो कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है, उसमें से कम से कम कुछ बातों को रद्द कर दें। शिक्षा किसी भी तरह की यथास्थिति को गम्भीर तौर पर उलटने और उसके प्रति ध्वंसकारी हो सकती है। वह लोगों को अपनी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को रद्द करने की ओर ले जा सकती है और इस तरह ऐसी पृष्ठभूमियों के निरन्तर अस्तित्व को ही खतरे में डाल सकती है। लेकिन अगर उदारवादी शिक्षा इस अर्थ में विध्वंसक या उलटफेर करने वाली है कि वह पुरानी निश्चितताओं को दी जाने वाली चुनौती को पोषित करती है, तो एक अन्य अर्थ में वह सामाजिक पुनरोत्पादन को अपना लक्ष्य बनाएगी। अनुदारवादी सांस्कृतिक और राजनैतिक समूह उदारवाद को सांयोगिक राजनैतिक सुविधा या उपयोगिता के तौर पर मौन स्वीकृति दे देते हैं। लेकिन उदारवादी समझौता तब तक जीवित नहीं रह पाएगा जब तक कम से कम कुछ लोग उसके मूल्यों का सकारात्मक समर्थन नहीं करते। इसलिए उदारवादी शिक्षा कम से कम यह आशा रखेगी कि शिक्षित होने वाले कुछ लोग ऐसी शिक्षा को मौजूदा स्थिति में एक आवश्यक तिकड़म या सहारे के रूप में नहीं देखेंगे बल्कि उसे स्वयं में और स्वयं के लिए अच्छी चीज के तौर पर देखेंगे।

आइये ऊपर चर्चा में आई कुछ बातों को मौजूदा उदारवादी विमर्श के संदर्भ के भीतर लाते हैं। जॉन रॉल्स महान आधुनिक राजनैतिक दार्शनिक हैं - शायद अकेले। उनकी पुस्तक 'थेअरी ऑव जस्टिस' (1971) ने एक लगभग मरणासन्न दर्शनशास्त्रीय विषय में जैसे जान फूंक दी और साथ ही पाठकों के लिए आधुनिक उदारवाद की रक्षा करते हुए विस्तृत, मौलिक और जोशीला बचाव-पक्ष प्रस्तुत किया। पिछले करीब 30 सालों में उन्होंने अपने मूल विचारों का बचाव करते हुए उनमें सुधार किया है और उनकी पुस्तक 'पॉलिटिकल लिबरलिज्म' (1993) यानी 'राजनैतिक उदारवाद' उससे पहले आई किताब के कई विषयों पर उनके बाद के विचार प्रस्तुत करती है। रॉल्स की उपलब्धियों पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। राजनैतिक उदारवाद का एक न्यूनतमवादी विचार उनके कार्य में निरन्तर चलने वाला विषय है। इस विचार के तहत अच्छे जीवन की अवधारणाओं के संदर्भ में राज्य की निष्पक्षता पर बल दिया जाता है और यह लगातार चिन्ता का विषय रहता है कि उदारवाद में निहित मूल्य - खास तौर से स्वायत्तता और व्यक्तिवादिता के मूल्य - केवल 'एक और सम्प्रदायी मत या सिद्धांत' बन कर न रह जाएं (रॉल्स 1985, पृष्ठ 246)। इस उद्देश्य से वे ऐसे मूल्यों को बढ़ावा देने वाले पूर्णतः विकसित उदारवाद को रद्द करते हैं और उसके एक कमजोर संस्करण का बचाव करते हैं। यह संस्करण शिक्षा से इस तरह के मूल्यों के समर्थन की आवश्यकता नहीं रखता बल्कि यह चाहता है :

''कहीं अधिक कम। इस उदारवाद के संस्करण, द्वारा कहा जाएगा कि बच्चों की शिक्षा में उनके संवैधानिक और नागरिक अधिकारों का ज्ञान शामिल रहे ताकि, मसलन, उन्हें मालूम रहे कि उनके समाज में अन्तरात्मा की आजादी मौजूद है और स्वधर्म-त्याग एक कानूनी जुर्म नहीं है - ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए, कि वयस्क हो जाने पर उनकी निरन्तर सदस्यता केवल मूल अधिकारों के बारे में उनकी अनभिज्ञता या अस्तित्वहीन जुर्मों के लिए सजा पर आधारित

न हो। इसके अलावा उनकी शिक्षा उन्हें समाज के पूर्ण रूप से सहयोगी सदस्यों के तौर पर रहने के लिए तैयार करे और आत्म-निर्भर रहने के काबिल बनने में मदद करे। उसे राजनैतिक गुणों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वे बाकी के समाज के साथ अपने संबंधों में सामाजिक सहयोग की न्याय संगत शर्तों का आदर करना चाहें।'' (1993, पृष्ठ 199-200)

अगर हम इसके दूसरे वाक्य को देखें तो इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो स्कूल के सूचनापट्ट पर बच्चों के मूल अधिकारों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हुई सूचना से भी की जा सकती है (कुछ उसी तरह जैसे इंग्लैण्ड के कारखानों में सूचनापट्टों पर फैक्ट्री-एक्ट की कॉपियां प्रदर्शित कर के किया जाता था)। लेकिन कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं सोचेगा कि बच्चों को चुनाव करने की सम्भावना के वास्तविक अनुभव से अवगत करवाने के लिए इतना भर पर्याप्त है। जिस जागरूकता की बात रॉल्स यहां करते हैं, वह न्यायोचित, तर्कसंगत शिक्षा के लिए एक शर्त हो सकती है लेकिन वह इस भूमिका को तब ही निभा सकती है अगर उसे ऐसी शैक्षिक प्रक्रियाओं में साकार किया जाए जो स्वायत्तता के हक में सक्रिय प्रतिबद्धता पर बल दें। इस उद्धरण का दूसरा भाग इससे भी अधिक अस्पष्ट एवं अनेकार्थी है, और कुछ सम्भावित पाठों पर पहले हिस्से के साथ ठीक नहीं बैठता। मसलन, अगर हम राजनैतिक गुणों को प्रोत्साहित करने की उनकी बात को गम्भीरता से लें ताकि बच्चे ''सामाजिक सहयोग की न्यायसंगत शर्तों का आदर करना चाहें'', तो यह ऐसी शिक्षा की बात दिखाई देती है जो उदारवादी गुणों को बढ़ावा देने से पूरी तरह जुड़ी हो एक ऐसी शिक्षा जो, जैसा कि हमने ऊपर कहा है, ऐसे लोग पैदा करना चाहती है जो उदारवाद का मूल्य समझते हैं न कि उसे केवल बर्दाश्त करते हैं।

राज्य के सक्रिय होने से संबद्ध यह अनिश्चितता - मसलन, शिक्षा के माध्यम से सक्रियता - उन्हें भी संक्रमित करती है, उन पर भी असर डालती है जो रॉल्स के बरअक्स, एक समग्र, सक्रिय उदारवाद के लिए दलील देने को तैयार हैं। मसलन, टॉमस नगेल 'इक्वैलिटी एण्ड पार्शियलिटी' में शिक्षा के संबंध में एक जगह कहते हैं : 'एक समाज को चाहिए कि वह जो कुछ भी बेहतरीन है, या जहां तक संभवतः अच्छा हो सकता है, उसकी रचना और सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश करे, और यह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उस सबका व्यापक प्रसार जो बस पर्याप्त भर है' (1991, पृष्ठ 135) यह हमारी कही गई बात की ही अनुगूंज है। लेकिन उसी किताब में बाद में वे लिखते हैं :

अपने नागरिकों की ओर से एक पात्र के रूप में राज्य की भूमिका उस समय प्रमुखता हासिल कर लेती है जब उसकी गतिविधि ऐसे मूल्यों के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित हो जो जीवन के अर्थ के बारे में कुछ नागरिकों के गहनतम दृढ़ विश्वासों के सीधे खण्डन में हो। मेरे विचार से यह बहुत ही अपमानजनक तथा अस्वीकार्य है और इससे राज्य द्वारा उनका प्रतिनिधित्व किये जाने का दावा जब्त हो जाता है। हां, दावा जब्त होने की यह बात इसी तरीके से उन अन्य मूल्यों को बढ़ावा दिए जाने पर लागू नहीं होती, जिनके साथ कुछ लोगों की सहमति न हो। (वही, पृष्ठ 167)

शिक्षा पर चर्चा के संदर्भ में जो यहां नगेल का संदर्भ नहीं है इस तरह का नजरिया दो आवश्यक बिन्दुओं को अनदेखा करता है। पहला यह, कि शिक्षा, अपने उस पूर्ण-विकसित समालोचनात्मक संस्करण में भी, जो हम प्रस्तुत कर रहे हैं, शिक्षित किए जा रहे लोगों के 'जीवन के अर्थ के बारे में... गहरे से गहरे विश्वासों' को किसी भी गम्भीर तौर पर खण्डित नहीं कर सकती। क्योंकि हमारी समझ में शिक्षा ऐसे अर्थ के बारे में चुनाव कर पाने की तैयारी है, जिसके चलते वह यह पहले से मान कर चलती है कि शिक्षित किए जा रहे व्यक्तियों ने अब तक तार्किक तौर पर इस क्षेत्र में चुनाव किया नहीं है। दूसरा, इस बात की बिल्कुल भी कोई गारण्टी नहीं दी जा सकती कि जिन्हें शिक्षित किया जा रहा है, उनके अभिभावकों के - और सामान्य तौर पर उनके सांस्कृतिक समूह के - पूरी तरह से रूप-आकार ले चुके पक्के विश्वास जीवन के अर्थ के उस प्रारूप या संस्करण को शामिल नहीं करेंगे जो उनके बच्चों के शिक्षित होने को रोकता हो या उस शिक्षा को नकारे जिसकी वकालत हम कर रहे हैं या उस शिक्षा के पहलुओं को नकारे उदाहरण के तौर पर, जेण्डर-समानता के लिए उसकी प्रतिबद्धता। यानी यह संभव है कि अभिभावक और उनके सांस्कृतिक समूह के

विश्वास मोटे तौर पर या तो अपने बच्चों की शिक्षा के ही पक्ष में न हों या किसी विशेष तरह की शिक्षा के या उसके कुछ पहलुओं के पक्ष में न हों, । और हमें लगता है कि इस तरह के लोग यह बताए जाने से शान्त नहीं हो जाएंगे कि ऐसी शिक्षा उनके लिए नहीं बल्कि बच्चों के लिए है, जिन्हें बस उनके बदले उनका स्थान लेने वालों के रूप में, नहीं देखा जाना है।

ऐसे हालात में उदारवादी राज्य या तो रॉल्स के रुख के एक संस्करण की ओर पीछे को जा सकता है, जिसमें कोई गम्भीर उदारवादी शिक्षा प्रस्तावित नहीं है, या और यह हमारा वरीयता-प्राप्त विकल्प है वह इस बात पर बल दे सकता है कि कुछ अभिभावकों की घोर नाराजगी और क्रोध के बावजूद राज्य से अनुदान-प्राप्त स्कूलों में सब बच्चे उदारवादी शिक्षा प्राप्त करें।

इस नुक्ते पर नगेल की असहजता इसी अध्याय में पहले जाहिर हो चुकी है जब वे शिक्षा का जिक्र करते हैं :

सच्चा उदारवादी रुख... राज्य की उस ताकत को नकारने के लिए प्रतिबद्धता का है, जिसके तहत वह व्यक्तिगत तौर से संकल्पित अच्छे जीवन पर पितृसुलभ तरीके से अपने नागरिकों पर कुछ भी थोप सके...

इस रुख के नतीजे जटिल हैं, क्योंकि कई तरीके हैं जिनसे राज्य अच्छे की परिकल्पना के लिए कार्यवाही कर सकता है और ये तरीके उन सबके लिए बराबर तौर पर अस्वीकार्य नहीं होंगे जो इस परिकल्पना में विश्वास नहीं रखते। (1) एक राज्य लोगों को तरजीह दी गई परिकल्पना के अनुकूल जीने के लिए बाध्य कर सकता है या उस तरह जीने से रोक सकता है जिसे वह निंदनीय मानता है। (2) राज्य तरजीह दी गई परिकल्पना के साकारीकरण को समर्थन दे सकता है, फिर वह चाहे शिक्षा हो या संसाधनों का आवंटन, और इस तरह वह सभी नागरिकों एवं कर-दाताओं को अप्रत्यक्ष तौर पर अपनी सेवा में शामिल कर लेता है। (3) राज्य अन्य कारणों से नीतियां अपना सकता है जिनके प्रभाव से एक परिकल्पना का किसी दूसरी के मुकाबले पूरा होना अधिक आसान हो सकता है। नतीजा यह, कि दूसरी के मुकाबले पहली की अनुपालना में अधिक प्रगति होगी।

स्पष्ट है कि पहला तरीका सबसे अधिक अनुचित है - इसके उदाहरण देते हुए धर्म की पालना की छूट, व्यक्तिगत जीवन की बुनियादी शैली या यौन संबंधी निजी बरताव पर प्रतिबंध की बात की जा सकती है। दूसरा तरीका प्रभावशाली एवं हावी मूल्यों के साथ साझापन महसूस न करने वाले व्यक्तियों पर फिर भी कम बड़ा हमला है लेकिन उसकी वैधता पर तो सवाल उठते हैं - इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण एक स्थापित चर्च को सार्वजनिक समर्थन का होगा। तीसरे तरीके से कुछ हद तक बचा ही नहीं जा सकता - उदाहरण के लिए, हालांकि उदारवादी सहनशीलता धर्म-निरपेक्षता को बढ़ावा देने और धार्मिक रूढ़िवादिता को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से प्रेरित नहीं है, इसके ये प्रभाव फिर भी पड़ सकते हैं। (वही, पृष्ठ 165-166)

मुख्य, महत्वपूर्ण श्रेणी यहां (2) है। नगेल इस नुक्ते पर शायद चूक गए कि इस श्रेणी के तहत शिक्षा की उनकी बात को कम से कम दो तरह से व्याख्यायित किया जा सकता है, जबकि इनमें से एक उन द्वारा परिभाषित उदाहरण के साथ मेल खाती है, और दूसरी मेल नहीं खाती। वे यह विचार रखने में सही हैं कि एक स्थापित चर्च के लिए राज्य का समर्थन उन लोगों के प्रति अपमानजनक और अप्रिय हो सकता है जो उस चर्च का हिस्सा नहीं हैं। और इस तरह के चर्च की सदस्यता के लिए तैयार करने वाली शिक्षा भी उतनी ही अप्रिय होगी। (इंग्लेण्ड की स्थिति, जहां ईश-निन्दा के कानून केवल ईसाई धर्म पर लागू होते हैं, भी उदारवाद के विरुद्ध जाती है। लेकिन जाहिर है कि इसका उदारवादी हल यह नहीं है कि इन कानूनों को सब धर्मों पर लागू कर दिया जाए, बल्कि हल तो यह है कि ईश-निन्दा के कानून हों ही नहीं)। लेकिन समालोचनात्मक बल वाली जिस तरह की उदारवादी शिक्षा का समर्थन हम कर रहे हैं, वह ऐसी तैयारी के ऐन उलट है। यह निश्चित तौर पर पितृमूलक है, लेकिन ऐसा कैसे न होता जबकि वह उन बच्चों के लिए बनाई गई है जिनके पास इस बात की संकल्पना ही नहीं है कि उनके लिए क्या अच्छा है - लेकिन इसका उद्देश्य शिक्षित

हो रहे लोगों को बस इस या उस चर्च के साथ तालमेल में रहने लायक बनाने का, या किसी के भी साथ तालमेल में न रहने लायक बनाने का नहीं है बल्कि जहां तक संभव हो, उपलब्ध धर्मो-विश्वासों में से किसी एक का तार्किकता से चुनाव कर पाने लायक बनाने का है, या इसके बाद कम से कम तार्किकता के साथ अपनी विशेष प्रतिबद्धताओं के हक में दलील दे पाने का है। यह सम्भव है - जैसा कि नगेल श्रेणी (3) के बारे में ध्यान दिलाते हैं - कि ऐसी शिक्षा-नीति, यह अर्थ देते हुए कि ऐसे सभी धर्म बराबर बौद्धिक कद के हैं, कम से कम अज्ञेयवाद (एग्नॉस्टिसिज्म) को प्रोत्साहन देने का प्रभाव छोड़े। लेकिन हमारे खयाल में यह उदारवादी शिक्षा की एक अच्छी तरह सोची-समझी नीति के अपरिहार्य नतीजों में से एक है।

बेशक, शिक्षा की इस तरह की अवधारणा की यह मांग नहीं हो सकती कि शिक्षित हुए लोग अपनी शिक्षा पूरी हो जाने के बाद उसकी विवेचनात्मक भावना को बचा कर रखें। बिन जांचे जीवन की ओर पलटना और पूर्वावस्था में आ जाना हमेशा एक वास्तविक सम्भावना हो सकती है। लेकिन जिस भी हद तक यह शिक्षार्थियों पर प्रभाव डालती है, उस हद तक यह सामाजिक जीवन के कई तौर-तरीकों, रीति-रिवाजों को उलट सकती है और लोगों को उनकी सामाजिक रीति-नीति और नियमों के लंगर से कुछ हद तक काट सकती है। कुछ मुद्दों पर शायद कोई तार्किक निर्णय न लिया जा सकता हो, और इन पर इस तरह की शिक्षा निष्पक्ष रहेगी। लेकिन यह निष्पक्षता पाठ्यचर्या के उन सब विषयों तक आवश्यक रूप से नहीं जाएगी जिन पर कुछ हितधारक समूहों का मानना हो कि कोई निर्णय लिया ही नहीं जा सकता। एक उदाहरण लें जैसे, फ्लैट अर्थ सोसायटीज - इस मान्यता वाले लोग कि धरती सपाट है - अब भी मौजूद हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इस तरह की सोसायटियों को पाठ्यचर्या में धरती के बारे में इससे अधिक प्रबुद्ध विचारों के साथ बराबर का स्थान मिलने का अधिकार है। यहां तो मसले का हल दलीलों से होगा। जैसा कि हमने कहीं और कहा है, यही बात विकासक्रम के सिद्धांत के प्रति सृष्टिवादी विरोध के संदर्भ में भी सही है। एक बार फिर, तार्किक वैज्ञानिक दलील हमें शिक्षण के लिए चुने जाने लायक विकल्प प्रदान करती है।

स्वतंत्रता

ऊपर व्याख्यायित उदारवाद के भीतर की असहमतियों और इन असहमतियों के भीतर शिक्षा के स्थान को लम्बे अरसे से चली आ रही सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता से संबद्ध बहस में भी स्थित किया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण बहस की शर्तें और मुख्य अन्तर इसाइया बर्लिन (1969) के आलेख 'टू कॉन्सेप्ट्स ऑव लिबर्टी' (स्वतंत्रता की दो अवधारणाएं) में पेश किए गए थे। बर्लिन नकारात्मक तथा सकारात्मक स्वतंत्रता में अन्तर करते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता मोटे तौर पर किसी व्यक्ति की क्रियाओं का अन्य लोगों की जबरदस्ती से स्वतंत्र होना है यानी दूसरों के दबाव के बिना कुछ करने की आजादी, और सकारात्मक स्वतंत्रता मोटे तौर पर आत्म-संयम या स्वयं पर नियंत्रण है। उदाहरण स्वरूप, बर्लिन के मुताबिक अगर अन्य लोग मेरी खुद की योजनाओं और परियोजनाओं को साकार करने की कोशिश में बाधा डालते हैं तो मैं वाजिब तौर पर स्वतंत्र न होने का दावा कर सकता हूं। लेकिन मैं पक्षी की तरह उड़ नहीं सकता, इस वजह से मैं स्वतंत्र न होने का दावा वाजिब तौर पर नहीं कर सकता। पक्षी वाले संदर्भ में सामर्थ्य की कमी का वास्तविक राजनैतिक स्वतंत्रता से कोई लेना-देना नहीं है, इसे तो वास्तविक राजनैतिक स्वतंत्रता के साथ खतरनाक तौर पर मिला दिया जाता है - यानी स्वतंत्रता के दो भिन्न रूपों को मिला दिया जाना। अर्थ यह, कि अगर मैं मूर्ख और अनजान हूं, मेरा इरादा पक्का नहीं है, तो मुझे अपनी अवस्था पर खेद तो हो सकता है, लेकिन सही में मैं स्वतंत्रता की कमी का रोना नहीं रो सकता।

बर्लिन के लिए राजनैतिक अच्छाई के रूप में केवल नकारात्मक स्वतंत्रता ही अनुसरण करने लायक है। किसी राजनैतिक सत्ता द्वारा सकारात्मक स्वतंत्रता का अनुसरण धीरे-धीरे लेकिन अनवरत रूप से सर्वसत्तावादी निरंकुशता की ओर ले जाता है : राजनैतिक सत्ता जब लोगों की खेदजनक झूठी चेतना को दुरुस्त करने की कोशिश करती है, और उसके फलस्वरूप - उदाहरण के लिए - उन द्वारा सच्ची वर्गीय नियति के साथ अभिन्न पहचान बनाए जाने की कमी या

आम-सामान्य स्वेच्छा के सच्चे उद्देश्यों की कमी को, उसी रूप में दुरुस्त करने की कोशिश करती है जिस रूप में सत्ता स्वयं उसे स्पष्ट तौर पर देखती है, तो सर्वसत्तावादी निरंकुशता की ओर जाने की दिशा तय हो जाती है। लोगों की इच्छाओं पर प्रतिक्रिया स्वरूप ध्यान देने की बजाए उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश में ऐसी हुकूमत हर तरह की वास्तविक आजादी को बहुत पीछे छोड़ देती है।

ऐसे विश्लेषण में बहुत कुछ है जो महत्वपूर्ण तौर पर सच है। लेकिन जैसा कि रॉल्स के वृत्तांत के साथ है, यहां भी दर्शाया गया अन्तर बहुत खुले तौर पर दिखाई देता है। रॉल्स की ही तरह इस विश्लेषण में मान कर चला गया है कि राजनैतिक व्यवस्थाएं पूर्ण रूप से विकसित हो कर आए स्वायत्त निर्वाचकों-विकल्पों के बीच चुनाव करने वालों, से बनती हैं, उसी तरह जैसे यूनानी मिथक के मुताबिक जुअस के सर से एथीना पूर्ण-विकसित रूप में जन्मी थी। इसलिए यह विश्लेषण यह सवाल कभी नहीं पूछता कि राजनीति का ऐसे निर्वाचकों को पैदा करने में कोई स्थान है भी कि नहीं। दूसरे शब्दों में, यह समाज में शिक्षा की भूमिका की तकरीबन पूरी तरह से अवहेलना करता है। लेकिन इस उपेक्षा से वह राजनैतिक स्वतंत्रता के कुछ पहलुओं की भी अवहेलना करता है। आत्म-संयम और नियंत्रण के कुछ तो पहलू जरूर हैं जिन्हें किसी भी सम्माननीय उदारवादी सिद्धांतकार को सम्बोधित करना ही चाहिए। जिस समाज में कुछ लोग उपयुक्त शिक्षा के अभाव में मूर्ख या अज्ञानी रह जाते हैं, हम वाजिब तौर पर उस समूह के सन्दर्भ में राजनैतिक स्वतंत्रता के अभाव की बात कर सकते हैं - जबकि इस अभाव को उसी समाज के भीतर अन्य लोगों द्वारा संबोधित किया जा सकता है । यहां जे. एस. मिल द्वारा 'ऑन लिबर्टी' में दी गई दलील महत्वपूर्ण है। इसके मुताबिक 'अनुभूति, अनुमान, विवेक-बोध, मानसिक गतिविधि के - यहां तक कि नैतिक पसंद के - मानव-गुण' एक 'इंसान के विशिष्ट गुण' हैं'; अगर इन्हें 'केवल चयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है' (पृ. 1859, 1968, पृष्ठ 116) तो जान-बूझकर, चाहे अनजाने में, ऐसी क्षमताओं को शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित और पोषित करने की उपेक्षा करने वाली कोई भी राजनैतिक व्यवस्था, कम से कम अपने कुछ लोगों की आजादी के विरुद्ध काम करने की आरोपी हो सकती है। स्वायत्तता के लिए शिक्षा की यही असल बात है, हम मान कर चलते हैं कि हमारे जैसे समाजों में एक सार्थक जीवन के लिए स्वायत्तता का होना आवश्यक है और हम बच्चों को अपने वयस्क जीवन में इसे प्रयोग करने के लिए तैयार करते हैं। ◆

(यह लेख क्रिस्टोफर विंच और जॉन गिंगेल की किताब 'Philosophy& Educational Policy A Critical Introduction' से लिया गया है।)

क्रिस्टोफर विंचः इंग्लैण्ड के जाने-माने समकालीन शिक्षा दार्शनिक और किंग्स कॉलेज, लंदन में शिक्षा दर्शन के प्रोफेसर।
जॉन गिंगेलः यूनिवर्सिटी कॉलेज नॉर्थम्पटन में दर्शनशास्त्र के विभागाध्यक्ष हैं।

टिप्पणीः

* विस्तार से जानने के लिए लेखकद्वय की पुस्तक 'Philosophy & Educational Policy A Critical Introduction' पढ़ें।
** वही